विचार बिन्दु

घृणा और प्रेम दोनों अंधे होते हैं। –कहावत

इतना हंगामा क्यूं है बरपा?

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड के आवास पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गणेश पूजा किए जाने का वीडियो जब से मीडिया में प्रसारित हुआ है, यह सार्वजनिक चर्चा और विवाद का विषय बन गया है। इस विवाद में कुछ लोग मुख्य न्यायाधीश को घसीटने से भी नहीं चूक रहे हैं।

सामान्यत: किसी भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के आवास पर धार्मिक समारोह में सम्मिलित होना कतई समाचार नहीं बनना चाहिए। क्योंकि, यहां प्रश्न कार्यपालिका के मुखिया प्रधानमंत्री एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है, यह विषय चर्चा में आना स्वाभाविक था। यह उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अधिकांश प्रकरणों में सरकार एक पक्ष होता है, विशेषकर केंद्र सरकार।

भारत की न्यायपालिका के बारे में कहा जाता है कि न्यायाधीशों को सामाजिक समारोहों में जाने और लोगों से मिलने से स्वयं को अलग रखना चाहिए ताकि उनके द्वारा दिए गए निर्णय न केवल निष्पक्ष हों अपितु ऐसे दिखाई भी दें। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार भी न्याय केवल होना ही पर्याप्त नहीं है उसका ऐसे होते हुए दिखाई देना भी आवश्यक है ।

यह चर्चा का विषय इसलिए भी बना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर गए हों। यदि प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के आवास पर चले भी जाते और उसका कोई वीडियो नहीं बनता एवं न उसे अपने ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री पोस्ट करके उसे वाइरल नहीं करते तो शायद इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस लेख में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह घटना क्या वास्तव में विवादास्पद है या इस बारे में राजनैतिक दलों द्वारा अनावश्यक विवाद उत्पन्न किया जा रहा है।

यह सही है कि यह पहली बार हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री किसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर इस प्रकार गए हों। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बालाकृष्णन अवश्य एक बार गए थे, किंतु वह एक ऐसा समारोह था, जिसमें अन्य कई व्यक्ति भी उपस्थित थे।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री ने वहां जाने की इच्छा व्यक्त की थी अथवा मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें अपने घर पर गणेश पूजा हेतु आमंत्रित किया था। मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र के निवासी हैं और वहां गणेश चतुर्थी का अत्यंत महत्त्व है। अनेक परिवार अपने घर में गणपति की स्थापना करते हैं और अनन्त चतुर्दशी या उससे पूर्व गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है।

यदि प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाने की पहल की थी तो, यह जानना रुचिकर होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय या मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है, जिसके अभाव में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।

कुछ समय बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र से हैं तो प्रधानमंत्री को यह उचित लगा कि मराठी परिधान में उनके आवास की गणेश पूजा का दृश्य सार्वजनिक रूप से प्रसारित होता है, तो उसका आगामी महाराष्ट्र चुनाव में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आगामी कुछ दिनों में केंद्र सरकार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरणों में निर्णय आने की संभावना है जैसे सेबी अध्यक्ष माधवी बुच का प्रकरण, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देने का मामला, रॉयल्टी संबंधी मामला जिससे केंद्र सरकार का बहुत बड़ा हित जुड़ा है।

यह भी हो सकता है कि केंद्र सरकार निकट भविष्य में कोई दूरगामी प्रभाव वाले महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही हो और जिनमें सुप्रीम कोर्ट के सकारात्मक रुख की अपेक्षा हो। यह उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय में अधिकांश मामलों में केंद्र सरकार पक्षकार होती है। यह स्वाभाविक सी बात है कि यदि किसी से निजी संबंध बनते हैं तो इसका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सोच पर आपके द्वारा दिए जाने वाले फैसले पर चाहे अनचाहे प्रभाव होने की आशंका तो बनी ही रहती है । शायद्र इसीलिए न्यायाधीशों को अधिक घुलने–मिलने से बचने की सलाह दी जाती है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में जारी आचरण संहिता में भी ऐसी ही अपेक्षा की गई है। न्यायाधीशों से अपेक्षित व्यवहार के बारे में एक अंग्रेजी वाक्य कहा जाता है "Judge should work like a horse and live like a hermit" अर्थात् न्यायाधीशों को कड़ी मेहनत से अपना काम करना चाहिए और संन्यासी जैसा जीवन जीना चाहिए।

इस प्रकरण का एक और पक्ष है, जिस पर भी विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री के अपने आवास पर गणेश पूजा के लिए आने और उसके दृश्यों के सार्वजनिक में कोई बुराई नहीं दिखाई दी। संभवतया, उन्हें अपने आत्मबल पर इतना विश्वास होगा कि प्रधानमंत्री के घर आने का उनके निर्णयों पर कतई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

न केवल प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश के आवास पर गए बल्कि उनके एवम् उनकी पत्नी साथ पूजा करते हुए उन प्रधानमंत्री का वीडियो वायरल हुआ जो साधारणतया फ्रेम में अपने अलावा किसी का आना कतई पसंद नहीं करते। मुख्य न्यायाधीश के साथ सार्वजनिक रूप से इस निकटता को बढ़ाने का संभावित कारण किसी को पता नहीं है ।

यह सब केवल अनुमान है और हो सकता है यह सब निराधार हो। सच्चाई तो आगामी दो माह में मुख्य न्यायाधीश के निर्णयों से ही पता चल पाएगी। सबकी नज़रें अब मुख्य न्यायाधीश पर रहेंगी।

डॉ चंद्रचूड के आवास पर प्रधानमंत्री का जाना इसलिए भी ध्यान आकर्षित करता है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की छवि बहुत ही निष्पक्ष और स्पष्ट वादी न्यायाधीश की रही है। उनके कुछ फैसले जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों का, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का, या चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को निरस्त करने का, मुख्य न्यायाधीश के निर्णयों से सरकार की किरकिरी हुई। डॉक्टर चंद्रचूड की छवि विद्वान विधि वेत्ता की भी रही है । इन्हें देश–विदेश में संबोधन करने हेतु आमंत्रित किया जाता रहा है और वे अपने विचार मीडिया पर बेबाकी से व्यक्त करते रहे हैं। इस कारण लोगों की अपेक्षाएं इनसे बहुत अधिक बन गई थीं। अपने अब तक के कार्यकाल में अपेक्षा अनुसार इन्होंने कार्य भी किया। उनके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, चण्डीगढ़ मेयर और खनिज रॉयल्टी के प्रकरणों में केंद्र सरकार की इच्छा के विपरीत निर्णय दिए गए। अब, इस एक प्रकरण से उनकी छवि पर प्रभाव पड़ा है, चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो ।

यह केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है कि क्या प्रधानमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाकर गणेश पूजा करके उन पर एक प्रकार का मानसिक दबाव बना दिया है।

पूर्व के कई उदाहरण हैं, जब मुख्य न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के कुछ समय बाद सरकार द्वारा उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दे दिया। रंजन गोगोई को सेवा निवृत्त होने के कुछ ही महीने बाद राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। इसी कारण यह अवधारणा बनी कि न्यायाधीशों द्वारा सरकार के प्रति नरम रुख रखने के प्रसाद स्वरूप उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कोई न कोई महत्वपूर्ण पद सरकार द्वारा दे दिया जाता है।

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश स्वयं एकाधिक बार कह चुके हैं कि न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात कुछ निश्चित अवधि तक उन्हें सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि 2 महीने बाद जब इनकी सेवानिवृत्ति होगी तो क्या उन्हें सरकार किसी प्रकार का प्रस्ताव देगी एवं क्या वे उसे स्वीकार करेंगे?

पाठकों को यह भी समझना होगा कि न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय विशेषकर मुख्य न्यायाधीश की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। कार्यपालिका के द्वारा बनाए कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। उसका निर्णय देश में कानून का रूप ले लेता है। सरकार में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा बनाए गए कानून को कई बार असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त किया है। इसी कारण इनसे यह अपेक्षा की गई कि, वे कार्यपालिका से निकटता नहीं बढ़ाएंगे एवं एक दूरी बनाए रखेंगे, ताकि वे बिना किसी संकोच के निष्पक्षता के साथ कानून एवं संविधान के अनुसार निर्णय दे सकें।

सरकार से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई करने वाली पीठ में आवश्यक नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश बैठें। यह बात सही भी है, किंतु कौन सा प्रकरण किस पीठ द्वारा सुना जाएगा, इसका निर्णय 'मास्टर ऑफ रोस्टर' होने के नाते मुख्य न्यायाधीश का है। यह सर्व विदित है कि विभिन्न न्यायाधीशों का रुख अलग होता है। यदि मुख्य न्यायाधीश का रुख सरकार के प्रति उदार हो तो वह महत्वपूर्ण प्रकरण, ऐसे न्यायाधीशों की पीठ को सौंप सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास है। इसी से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने कुछ वर्षों पहले एक संवाददाता सम्मेलन करके तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप लगाए थे। इनमें न्यायाधीश रंजन गोगोई भी सम्मिलित थे जो बाद में मुख्य न्यायाधीश बने और सेवा निवृत्ति के बाद राज्यसभा के सदस्य बने।

प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश के घर पर जाने एवं इसके दृश्य मीडिया के द्वारा प्रसारित करने पर सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि महाराष्ट्र के दलबदल संबंधित प्रकरण से मुख्य न्यायाधीश को स्वयं को अलग कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ वकीलों ने तो मुख्य न्यायाधीश के त्यागपत्र तक की मांग कर ली है। कुल मिलाकर मुख्य न्यायाधीश की स्थिति अटपटी सी हो गई है। मुख्य न्यायाधीश इस पूरी घटना के संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी करें तो शायद इस विवाद पर विराम लग सकता है। अभी मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के लगभग 55 दिन शेष हैं । प्रत्येक दिन, उनके द्वारा दिए गए निर्णय एवम टिप्पणियों पर देश के नागरिकों की, विशेष कर अधिवक्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों की नज़र रहेगी।

इस प्रकरण का एक और पक्ष है, जिस पर भी विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री के अपने आवास पर गणेश पूजा के लिए आने और उसके दृश्यों के सार्वजनिक में कोई बुराई नहीं दिखाई दी। संभवतया, उन्हें अपने आत्मबल पर इतना विश्वास होगा कि प्रधानमंत्री के घर आने का उनके निर्णयों पर कतई प्रभाव नहीं पडेगा। शासकों द्वारा अपने परिजनों के विरुद्ध निर्णय देने के कई उदाहरण इतिहास में उपलब्ध हैं। यह व्यक्ति की निष्ठा पर निर्भर करता है कि उसका नैतिक साहस किस स्तर का है। इस प्रकरण में हो रहे विवाद पर बस यही कहने का मन करता है कि **''हंगामा क्यों है बरपा?''**

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

आखिर कार्बन उत्सर्जन का नियंत्रण क्यों जरूरी है

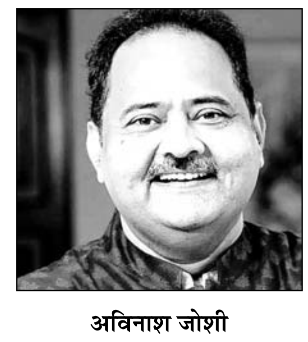

अविनाश जोशी

कार्बन व्यापार में चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया बड़े निर्यातक हैं। इन देशों में जिन कंपनियों का कार्बन उत्सर्जन देश के सालाना कार्बन उत्सर्जन का साठ फीसद से ज्यादा है, वे अपने उत्सर्जन की भरपाई 'कार्बन क्रेडिट' खरीद कर करना आसान मानती हैं। प्रति इकाई 'कार्बन क्रेडिट' के बाजार भाव में मांग के अनुसार उतार–चढ़ाव आता रहता है। मसलन, चीन में सरकार की कार्बन उत्सर्जन रोकने पर सख्ती की नीति के कारण उद्योग 'कार्बन क्रेडिट' खरीदने की होड़ में हैं।

एक रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2021 में कुल कार्बन उत्सर्जन के आधे हिस्से में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश शामिल थे। इस मामले में भारत का योगदान महज सात फीसद है, जबकि चीन इकतीस फीसद कार्बन उत्सर्जन करता है जो अपने आप में सर्वाधिक है। विश्व के सभी देशों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन काफी तेज गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तापमान में होनें वाली इस वृद्धि में सबसे अधिक योगदान कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का है। जिन देशों में औद्योगिक गतिविधियाँ ज्यादा होतीं है, वहां कार्बन का उत्सर्जन अधिक होता है। क्योटो प्रोटोकोल एक ऐसी ही संधि है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विश्व के विकसित और विकासशील देशों को बाध्य करती है।

अमेरिका जैसे देश अमेरिका प्रथम की नीति पर चलते हैं, जबकि भारत जैसे देश 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत को अपनाते हैं। यही कारण है कि सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले अमेरिका जैसे देश औद्योगिकीकरण और विकास को सर्वोपरि लक्ष्य बनाए हुए हैं। जब कभी विकास की ओर नई प्रगति होती है तो उसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है और यही असर एक आदत का रूप ले ले, तो दुष्प्रभाव की पूरी संभावना बन जाती है। ऐसे दुष्प्रभाव से समय रहते निपटा न जाए तो पृथ्वी और उसके जीव अस्तित्व को लेकर एक नई चुनौती से गुजरने लगते हैं।

भारत में कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कई नीतियाँ और उपायों की प्राथमिकता दी जा रही है भारत सरकार ने वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 'निगेलेशन स्ट्रेटेजी 2030' जैसी पहलों को प्रोत्साहित किया है, जो विद्युत, वायुमार्गों, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। भारत ने नवाचारी और स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतों के प्रति विशेष ध्यान दिया है, जैसे कि सौर ऊर्जा और जल परियोजनाएँ, जो कार्बन नकारात्मक योगदान को बढ़ावा देती हैं। वनस्पति संरक्षण और वन्यजीव सुरक्षा के उपायों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वनस्पतियों और वन्यजीवों का संरक्षण भी कार्बन संकेत को संभावित रूप से कम कर सकता है। भारत सरकार ने कार्बन कैचर और स्टोरेज (ण्णए) प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को अवरुद्ध किया जा सकता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं।

कार्बन उत्सर्जन से यहा तात्पर्य कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, और अन्य प्रकार के कार्बन का वायुमंडल में उत्सर्जन से है। ये उत्सर्जन मुख्य रूप से वाहनों की इंधन जलाने, उर्जा उत्पादन, और औद्योगिक गतिविधियों से होता है, जिसके परिणामस्वरूप वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का स्तर बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारकों में से एक बनता है मानव द्वारा किये जा रहे उत्सर्जन के कारण औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान पहले ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और कार्बन उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि से हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी और अधिक खतरनाक जगह साबित होगी।

हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे–छोटे बदलाव करके कार्बन उत्सर्जन में कमी कर सकते है, जैसे सौर, पवन ऊर्जा के इस्तेमाल और पौधारोपण आदि से कार्बन उत्सर्जन में कमी की जा सकती है। कार्बन उत्सर्जन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का वातावरण में ईंधन, कच्चे तेल और कोयले के जलने से होता है। घर में बिजली के अधिक प्रयोग से और फ्लोरेसेंट बल्बों के इस्तेमाल से कर्मी की जा सकती है। ग्लास, धातुओं, प्लास्टिक और कागज को एक से अधिक बार उपयोग में ला कर भी हम कमी कर सकते हैं, इसके साथ ही निरंतर चलनें वाले रेफ्रिजरेटर की स्पीड धीमी रख कर या घर की दीवारों पर हल्के रंग का पेंट भी इसमें काफी मददगार होते है। वैसे तो इंडिकेटर और स्टैंडबाय मोड पर रहनें वाले गैजेट्स भी कई किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। कुछ छोटी–छोटी बाते एवं आदते भी सहायक हो सकती है जैसे उचित मात्रा में कपड़े एकत्र होनें पर ही वाशिंग मशीन का उपयोग करे, गाड़ी के टायरों में हवा सही रखकर लगभग तीन प्रतिशत ईंधन की बचत कर सकते हैं, अधिक से अधिक वृक्ष लगानें का प्रयास करे, क्योंकि एक अकेला वृक्ष अपनी जिन्दगी में एक टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है,भोजन को बर्बाद करनें से बचे, क्योंकि इसे तैयार करने में काफी ऊर्जा का उपयोग होता है इस तरह हम प्रकृति एवम पर्यावरण के प्रति जागरूक समाज के निर्माण में सहायक हो सकते है।

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इस मसले पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं और उनमें वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी के कारणों और उसके समाधान पर विचार किया जाता है। लेकिन जमीनी स्तर पर इस सबका हासिल क्या रहा है, यह छिपा नहीं है। हालत यह है कि तापमान में बढ़ोतरी की समस्या अब ऐसी शक्ल अख्तियार करती जा रही है,जिसमें ऐसा लगता है मानो बहुत कुछ हाथ से छूट रहा हो। पिछले कुछ समय से मौसम के अति कठोर होते जाने की वजहें तापमान के इसी उतार–चढ़ाव में छिपी हैं। अमेरिका के दक्षिण–पश्चिम और मेक्सिको में जानलेवा गर्म हवाएं चल रही हैं तो यह बेवजह नहीं हैं। अब अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ते तापमान की वजह से बिगड़ते हालात की खबरें आ रही हैं, तो यह एक तरह से गहराती समस्या की ही कड़ियां हैं। विडंबना यह है कि आए दिन होने वाली बैठकों में वैज्ञानिक और पर्यावरणविद जलवायु में आती विकृति के लिए कोयला, तेल और प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन के उपयोग से जलवायु की निरंतरता में होने वाले बदलाव को जिम्मेदार ठहराते हैं। तात्कालिक स्तर पर इस मसले के हल के लिए कुछ बिंदुओं पर सहमति भी बनती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है।

कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया के ज्यादातर देशों में पूर्णबंदी लगी थी, तब कार्बन उत्सर्जन में न केवल गिरावट आई थी, बल्कि आसमान कहीं अधिक साफ और प्रदूषण मुक्त देखने को मिला था। दरअसल कार्बन उत्सर्जन को लेकर दुनिया के देशों में कभी एकजुटता देखने को मिली ही नहीं। विकसित और विकासशील देशों में इसे लेकर आरोप–प्रत्यारोप भी व्यापक पैमाने पर रहे हैं। इतना ही नहीं, कार्बन उत्सर्जन को लेकर सभी देश बढ़–चढ़ कर अंकुश लगाने की बात करते रहे और हकीकत में नतीजे इसके विपरीत बने रहे। पृथ्वी साढ़े चार अरब साल पुरानी है और कई कालखंडों से गुजरते हुए मौजूदा पर्यावरण में है। यदि इससे वाकई बचना है तो वैश्विक उत्सर्जन में हर साल औसतन एक सौ चालीस करोड़ टन की कटौती करनी होगी तब कहीं जाकर 2070 तक कार्बन उत्सर्जन के मामले में शून्य तक पहुंचा जा सकेगा। कार्बन उत्सर्जन से उत्पन्न समस्या निजी नहीं है और दुनिया के देश भले ही आर्थिक संपन्नता और सभ्यता के चरम पर हों, मगर पृथ्वी को उसी की भांति बनाए रखने में यदि सफल नहीं होते हैं तो दुनिया को इसकी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा।

भारत की अपनी चिंताएं हैं। एक तरफ जहां करोड़ों लोगों को भुखमरी और गरीबी से बाहर निकालना है जिसके लिए आर्थिक विकास अपरिहार्य है, तो दूसरी ओर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी कमी लाना है। ये दोनों दृष्टिकोण एक–दूसरे के अंतर्विरोधी हैं। यही कारण है कि भारत सौर और पवन ऊर्जा के विस्तार से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का रास्ता भी खोज रहा है। वास्तव में कार्बन उत्सर्जन में कटौती को लेकर सम्मेलनों में साहस दिखाने वाले देशों की कमी नहीं है, मगर देश के भीतर आर्थिक विकास की आपा–धापी के चलते वायदों पर भी खरे नहीं उतर पाते हैं

–अविनाश जोशी,
स्वंतत्र पत्रकार एवम लेखक

प्रयास संस्थान चूरू ने राजस्थानी भाषा के आठ साहित्यकारों को सम्मानित किया

राजस्थानी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए : सांसद कस्वां

जयपुर। प्रयास संस्थान चूरू द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार शृंखला के तहत सूचना केंद्र चूरू में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के आठ राजस्थानी भाषा के प्रमुख साहित्यकारों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

संस्थान के सचिव कमल शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर चूरू के सुरेंद्र पारीक रोहित को मोहन आलोक साहित्य सम्मान, उदयपुर के अरविंद आशिया एवं कोटा के जितेंद्र निर्मोही को बैजनाथ पंवार कथा साहित्य पुरस्कार, बीकानेर की मोनिका गौड़ एवं जोधपुर की बसंती पंवार को सावित्री चौधरी खूमसिंह साहित्य पुरस्कार, जैसलमेर के महेंद्र सिंह छायण एवं श्रीडूंगरगढ़ के पूनमचंद गोदारा को दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार से अलंकृत किया गया। राजस्थानी साहित्य पुरस्कार समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि, सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि राजस्थानी भाषा एक समृद्ध और प्राचीन भाषा है, इस भाषा का समृद्ध आधुनिक साहित्य है। यह भाषा राजस्थान की लोक संस्कृति की वाहक है, इसके संरक्षण एवं संवर्धन के हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए। राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिलवाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर, संसदीय कमेटी तथा संसद में सक्रियता से बात रखने का मेरा प्रयत्न रहेगा। सांसद कस्वां ने कहा कि राजस्थानी आंदोलन से जुड़े लोग एवं साहित्यकार, बुद्धिजीवी इस दिशा में मार्गदर्शन करेंगे तो वे चार कदम आगे चलकर यात्रा तय करेंगे।

सूचना केंद्र चूरू में आयोजित समारोह में प्रदेश के राजस्थानी भाषा के आठ साहित्यकारों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

- **चूरू के सुरेंद्र पारीक रोहित को मोहन आलोक साहित्य सम्मान, उदयपुर के अरविंद आशिया एवं कोटा के जितेंद्र निर्मोही को बैजनाथ पंवार कथा साहित्य पुरस्कार से नवाजा**
- **बीकानेर की मोनिका गौड़ एवं जोधपुर की बसंती पंवार को सावित्री चौधरी खूमसिंह साहित्य पुरस्कार, जैसलमेर के महेंद्र सिंह छायण एवं श्रीडूंगरगढ के पूनमचंद गोदारा को दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार से अलंकृत किया गया**

समारोह की अध्यक्षता करते हुए भारत सरकार की साहित्य अकादमी में राजस्थानी भाषा संयोजक प्रो. अर्जुनदेव चारण ने कहा कि राजस्थानी की बात करना यहां की संस्कृति, रोजगार और लोक की बात करना है। प्रख्यात साहित्यकार डॉ. भरत ओला ने बतौर विशिष्ट अतिथि बोलते हुए कहा कि भाषा की मान्यता किसी व्यक्ति, किसी सांसद का निजी मसला भी होना चाहिए और प्रांत का सामूहिक मसला भी। कोई सांसद आगे आकर इसे संभालेगा तो तय है कि समय उसे याद करेगा। साहित्यकार और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभागाध्यक्ष डॉ. गजेसिंह राजपुरोहित ने कहा कि मां से जैसे हमारा सम्बन्ध है, वैसे ही मातृभाषा से भी हमारा होना है, हमें भाषा की अंवेर करनी होगी। जिस–जिस ने भाषा की अंवेर की अंजसजोग रहा कि वह प्रगति के पथ की ओर ही अग्रसर हुआ।

समारोह में प्रो. हनुमानाराम ईसराण, प्रो. कमल सिंह कोठारी, राजकुमार लाटा, उम्मेद गोठवाल, सुमेरसिंह, विकास मील, हेमंत सिहाग, बनवारी खामोश, श्यामसुंदर शर्मा, राजेंद्र मुसाफिर, अशोक डूडी, मुकेश ईसराण, रियाजत अली खान, शेरखान मलकांण, धर्मेंद्र बुडानिया, जमील चौहान, योगेश ढाका, मोहन सोनी, देवीलाल महिया, जयसिंह पूनिया, संजय कुमार, नरेंद्र सिहाग, मंजु पंवार, शिवकुमार सैनी, गीता रावत, स्नेहलता शर्मा, तनजीम खान, उम्मेद धानिया, कृशणा जाखड़, नानकराम डूडी, मोहन अर्जुन, सुधींद्र सुधि, हरिसिंह सिरसला आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में बड़ी संख्या में साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे।

प्रारम्भ में प्रयास संस्थान के अध्यक्ष और जाने–माने साहित्यकार डॉ. दुलाराम सहारण ने स्वागत करते हुए आयोजन विषयक जानकारी दी। सचिव कमल शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन साहित्यकार डॉ. हाकम अली नागरा ने किया।

राशिफल मंगलवार 17 सितम्बर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, चतुरदशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, शतभिषा नक्षत्र दिन 1:53 तक, धृति योग प्रात: 7:44 तक, वणिज करण दिन 11:45 तक, चन्द्रमा बुधवार प्रात: 5:44 पर मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–कन्या, चन्द्रमा–कुम्भ, मंगल–मिथुन, बुध–सिंह, गुरू–वृष, शुक्र–कन्या, शनि–कुम्भ, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

आज रवियोग दिन 1:53 तक है। भद्रा दिन 11:45 से रात्रि 9:54 तक रहेगी। आज अनन्त चतुर्दशी व्रत, चान्द पूर्णिमा व्रत, पंचक्रम, विश्वकर्मा पूजा है। आज सन्यासियों का चातुर्मास पूर्ण होगा। आज पूर्णिमा, पौष्ठपदी श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:19 से 10:50 तक, लाभ–अमृत 10:50 से 1:53 तक, शुभ 3:24 से 4:55 तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:17, सूर्यास्त 6:26

मेष
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी और भय बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा।

वृष
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

सिंह
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

कन्या
घर–परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का तनाव दूर होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

धनु
घर–परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है।

मीन
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है।